

MSME EPC ने निजी निवेश में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट पर चिंता व्यक्त की है

उत्तराखंड से लोगों के निरंतर पलायन को रोकने के लिए, राज्य सरकार को निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए तत्काल एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जो साल दर साल गिरता जा रहा है, संघर्षरत सूक्ष्म और लघु इकाइयों को बचाने और कृषि आधारित उद्योगों के साथ-साथ जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा "उत्तराखंड में विकास और विकास - उभरते निवेश के अवसर" पर किए गए एक अध्ययन में, यह बताया गया है कि राज्य में विशेष रूप से युवाओं के लिए वर्तमान परिदृश्य चिंताजनक प्रतीत होता है और इसलिए, गंभीर सोच-विचार करने की आवश्यकता है। अध्ययन को आज यहां इसके अध्यक्ष डॉ डी एस रावत ने जारी किया।

डॉ रावत ने कहा कि हालांकि वर्तमान में लगभग 58,000 एमएसएमई लगभग 6.5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन इसके यादृच्छिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि उनमें से कई ने अपने शटर बंद कर दिए हैं और कई समय पर किफायती ऋण की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। , और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता।

जबकि 2020-21 में, सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा घोषित कुल नई निवेश परियोजनाएं 2153.59 करोड़ रुपये की थीं, 2021-22 में नई घोषित परियोजनाएं 5459.88 करोड़ रुपये की थीं। 2018-19 में घोषित नई निवेश परियोजनाएं 6743.48 करोड़ रुपये की थीं, और 2019-20 में 4204.25 करोड़ रुपये की थीं।

2018-19 में कुल बकाया निवेश परियोजनाएं (पीओ) 264493.92 करोड़ रुपये और कार्यान्वयन के तहत (यूआई) 138523.64 करोड़ रुपये, क्रमशः 243950.54 करोड़ रुपये (पीओ) और 1313392.52 करोड़ रुपये (यूआई) थीं।

जबकि 2021-22 में कुल बकाया निवेश परियोजनाएं 243549.47 करोड़ रुपये की थीं और कार्यान्वयन के तहत 136491.55 करोड़ रुपये और 2020-21 में क्रमशः 265187.62 करोड़ रुपये (पीओ) और 135978.79 करोड़ रुपये (यूआई) थीं।

अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक परियोजना की समीक्षा और जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए और परियोजना लागत में होने वाली किसी भी देरी से बचने के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए।

एमएसएमई क्षेत्र राज्य में अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर सकता है और रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), निर्यात और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। राज्य में एमएसएमई प्रमुख रूप से पर्यटन और आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, फूलों की खेती, प्राकृतिक फाइबर, फार्मास्यूटिकल्स, कल्याण और आयुष पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

एमएसएमई ईपीसी ने नॉलेज फर्म बिलमार्ट फिनटेक के साथ सूक्ष्म, लघु, मध्यम, स्टार्ट-अप, कला और शिल्प क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए दो जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेने का प्रस्ताव दिया है ताकि उद्यमशीलता कौशल और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज्ञान का उन्नयन किया जा सके। व्यवसायों की वृद्धि।

डॉ. रावत ने कहा, एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजित कर पलायन की समस्या को कम कर सकता है, राज्य में प्रवासित आबादी को वापस आकर्षित कर सकता है। राज्य को "पर्यटन स्थल" के रूप में विकसित और प्रचारित किया जाना चाहिए और इसलिए चार पर्यटन स्थलों की पहचान, भूमि अधिग्रहण और निर्धारित समय सीमा के भीतर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इन स्थलों को बढ़ावा देना चाहिए। ये पर्यटन स्थल राज्य की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाएंगे और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेंगे।

चूंकि पहाड़ी राज्य में कृषि करना उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों से नुकसानदेह हो गया है, इसलिए पूरे पहाड़ी राज्य को 'जैविक राज्य' के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जो आकर्षक नीतिगत पहलों द्वारा समर्थित है, और किसानों/व्यापारियों और अन्य लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। हालांकि 'जैविक नीति' लागू है, इसे लागू नहीं किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि चाय, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और "ब्रांड उत्तराखंड चाय" बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
